

## To develop Oxy-Forest

119 Sh. NEERAJ SHARMA (Faridabad Nit):

Will the Forest & Wildlife Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that a proposal has been received by the Forest Department for developing an Oxy-forest on the vacant land of the Rehabilitation Department near Dabua Vegetable Market in Faridabad; and
- b) the reasons for not developing the said Oxy-forest so far, together with the time by which the said Oxy-forest is likely to be developed?

**Reply: Kanwar Pal, Forest and Wildlife Minister, Haryana**

- a) Yes Sir. The Forest Department has received a proposal for developing an Oxy-Forest on the land of the Rehabilitation Department near Dabua Vegetable Market in Faridabad.
- b) The Deputy Commissioner, Faridabad vide his letter no. 560 dated 17.08.2021 (Copy enclosed) has informed that the land at Dabua Mandi, initially proposed for the Oxy-Forest project, was under the Rehabilitation Department and had been allocated for commercial development since 1991. This area now comprises shop-cum-flats built and auctioned by the Rehabilitation Department. Due to these pre-existing commitments and developments, the land could not be transferred to the Forest Department. **As the transfer of land to Forest Department is a requisite for developing the Oxy-Forest, the project is not feasible at this location.**

## ऑक्सी-वन विकसित करना

119 श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद नीट):

क्या वन एवं वन्यजीव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद में डबुआ सब्जी मंडी के पास पुनर्वास विभाग की खाली जमीन पर ऑक्सी-वन विकसित करने का प्रस्ताव वन विभाग को प्राप्त हुआ है, और
- ख) उक्त ऑक्सी-वन अब तक विकसित न होने के क्या कारण हैं, साथ ही उक्त ऑक्सी-वन कब तक विकसित होने की संभावना है?

**उत्तर: कंवर पाल, वन एवं वन्यजीव मंत्री, हरियाणा**

- क) जी श्रीमान, वन विभाग को फरीदाबाद के डबुआ सब्जी बाजार के पास पुनर्वास विभाग की जमीन पर एक ऑक्सी-वन विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
- ख) उपायुक्त, फरीदाबाद ने अपने पत्र संख्या 560 दिनांक 17.08.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया है कि डबुआ मंडी में ऑक्सी-वन परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि पुनर्वास विभाग के अधीन थी और उसे 1991 से वाणिज्यिक विकास के लिए आवंटित किया गया था। अब यह क्षेत्र पुनर्वास विभाग द्वारा निर्मित और नीलाम किए गए दुकान और फ्लैट्स से युक्त है। इन पूर्ववर्ती प्रतिबद्धताओं और विकास के कारण, यह जमीन वन विभाग को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। **चूँकि ऑक्सी-वन विकसित करने के लिए वन विभाग को जमीन का हस्तांतरण आवश्यक है। अतः इस स्थान पर ऑक्सी-वन बनाना संभव नहीं है।**